

2030 तक भारत की हरति नविश क्षमता \$3 ट्रिलियन होने की संभावना

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय वित्त नगिम (International Finance Corporation) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि भारत में 2018 से 2030 तक जलवायु के क्षेत्र में 3 ट्रिलियन डॉलर नविश प्राप्त करने की क्षमता है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में हरति इमारत (Green Buildings) निर्माण एक ऐसा क्षेत्र साबित हो सकता है, जो सर्वाधिक नविश को आकर्षित कर सकता है।
- इसका कारण यह है कि 2030 तक हमें जिस प्रकार की हरति इमारतों की आवश्यकता होगी, उनमें से 70% का निर्माण किया जाना अभी शेष है।
- इस क्षेत्र में 20 मिलियन घर शहरी क्षेत्रों में तथा 10 मिलियन घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने की आवश्यकता है, तब जाकर सरकार के '2022 तक सभी के लिये घर' के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।
- IFC ने यह अनुमान लगाया है कि भारत में हरति इमारत निर्माण में 1.4 ट्रिलियन डॉलर के नविश प्राप्त करने की क्षमता वदियमान है, जिसमें से 1.25 ट्रिलियन डॉलर का नविश आवासीय निर्माण में तथा 228 बिलियन डॉलर का नविश वाणिज्यिक इमारतों के निर्माण में संभावित है।
- हरति इमारतों के अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, जो नविशकों को आकर्षित कर सकता है।
- हाल ही में सरकार ने भी संभावना जताई है कि 2030 में विक्रय की जाने वाली सभी नई कारें इलेक्ट्रिक होनी चाहिये।

वभिन्न क्षेत्रों में हरति नविश की संभावना

बाधाएँ-

IFC की रिपोर्ट भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति में कुछ बाधाओं की भी बात करती है, जिसे नीचे दर्शाए गए रेखाचित्र से समझ सकते हैं-

तुलनात्मक अध्ययन-

पाकिस्तान को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देश भी हरति नविश की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं।

- बांग्लादेश- \$ 172 बिलियन
- नेपाल - \$ 46 बिलियन
- भूटान- \$ 42 बिलियन
- श्रीलंका- \$ 18 बिलियन
- मालदीव- \$ 2 बिलियन

नष्कर्ष

भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 2005 के उत्सर्जन की तुलना में 35% घटाने का संकल्प लिया है। अतः भारत को अपने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति के लिये वभिन्न क्षेत्रों जैसे-कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना तथा परिवहन में बड़े नविश की आवश्यकता होगी।